बजट मोदी सरकार का
गाँव, गरीब, किसान का

कृषि उन्नति
हमारी प्राथमिकता

किसान हित को समर्पित मोदी सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
भारत सरकार

On declaration of black money 7.5% Kisan Kalyan Surcharge will be levied

BUDGET SUMMARY

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

Sl. No.	Department Of Agriculture & Cooperation	RE 15-16 (Crore Rs.)	RE 16-17 (Crore Rs.)	% Change From RE
SCHEME				
1	Prime Minister Crop Insurance Scheme	3185.05	5500.00	72.68%
2	National Agriculture Development Scheme	3900.00	5400.00	38.46%
3	Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana	1550.01	2340.00	50.97%
4	Agriculture Growth Scheme	6864.90	7159.90	4.3%
	Total schemes	15,500	20,400.00	33.27%
Non-Plan				
5	Subsidy to farmers for short termed debt	0	15,000	
6	Other Non Plans	309.54	583.69	88.56%
	Total Non Plans	309.54	15,583.69	
	Total	15,809.54	35,983.69	127%

1	Department of Livestock, Dairy & Fisheries	1491	1600	7.3%
2	Indian Agriculture Research Council/Institute	5385.21	6306.89	17%

- To set up a long period irrigation fund with the sum of Rs. 20,000 crores in 2016-2017 by NABARD.
- Long time pending 89 irrigation projects under extensive and mid irrigation schemes through which 80.6 lakh hectare area will be irrigated with a cost of 86500 crore rupees for the next five years out of which 12517 crore rupees have been incurred to implementation of 23 schemes during the year 2016-2017.
- 5 lakh farm ponds and wells will be arranged in rainfed areas under MANREGA.
- 10 lakh compost pits will be constructed to produce organic manure under MANREGA.
- An additional allotment of rupees 500 crore for the year 2016-2017 so as to enhance the productivity of pulses.
- 9.0 lakh crore rupees allocation in the year 2016-2017 by increasing 6% as against 8.50 lakh crore rupees in the year 2015-2016 for debt meant for debt flow to enhance milk productivity for four new schemes i.e. “Livestock Sanjeevni”, “Nakul Health Card”, “E-Livestock Haat”, “National Indigenous Breed Genomic Centre”.

काले धन के खुलासे पर देना होगा 7.50 प्रतिशत किसान कल्याण सरचार्ज

बजट सारांश

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

क्र. सं.	कृषि एवं सहकारिता विभाग	आर.ई. 15–16 (करोड़)	बी.ई. 16–17 (करोड़)	प्रतिशत परिवर्तन (आर.ई. से)
योजना				
1	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना	3185.05	5500.00	72.68%
2	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	3900.00	5400.00	38.46%
3	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	1550.01	2340.00	50.97%
4	कृषि उन्नती योजना	6864.90	7159.90	4.3%
	कुल योजना	15,500	20,400.00	33.27%
गैर–योजना				
5	किसानो के अल्पावधिक ऋण के लिए सब्सिडी	0	15,000	
6	अन्य गैर योजनाएं	309.54	583.69	88.56%
	कुल गैर योजना	309.54	15,583.69	
	कुल	15,809.54	35,983.69	127%

1	पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्यपालन विभाग	1491	1600	7.3%
2	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद / संस्थान	5385.21	6306.89	17%

- नाबार्ड द्वारा वर्ष 2016–17 में 20,000 करोड़ रूपये का दीर्घावधि सिंचाई कोष की स्थापाना।
- वृहत् एवं मध्यम सिंचाई योजनाओं के तहत लम्बे समय से लम्बित 89 सिंचाई परियोजनाएं, जिससे अगले 5 वर्षों में 86,500 करोड़ रूपये की राशि से 80.6 लाख हैक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई होगी, में से वर्ष 2016–17 में 12,517 करोड़ रूपये की राशि से 23 योजनाएं पूर्ण करने के लिए प्रावधान किया गया है।
- मनरेगा के तहत वर्षपोषित क्षेत्रों में 5 लाख फार्म तालाबों और कुओं की व्यवस्था होगी।
- मनरेगा के तहत जैविक खाद के उत्पादन के लिए 10 लाख कम्पोस्ट गढ्ढों का निर्माण किया जायेगा।
- दलहन की उत्पादकता बढाने के लिए वर्ष 2016–17 हेतु अतिरिक्त 500 करोड़ का आवंटन।
- ऋण प्रवाह हेतु वर्ष 2015–16 के मुकाबले 8.50 लाख करोड़ से 6 प्रतिशत बढ़ाकर वर्ष 2016–17 में 9.0 लाख करोड़ का आवंटन।
- दुग्ध उत्पादन बढाने के लिए चार नई योजनएं 'पशुधन संजीवनी', 'नकुल स्वास्थ्य पत्र', 'ई–पशुधन हाट' और 'राष्ट्रीय देशी नस्ल जेनोमिक केन्द्र हेतु अतिरिक्त 850 करोड़ रूपये का आवंटन।

विकास बजटः प्रमुख महत्वपूर्ण बिंदु

बजट हर एक के सम्मान का।
गाँव, गरीब, किसान का।
भारत की उड़ान का।

भारत को बदलने के लिए 15 महत्वपूर्ण सुधारः

1. **कृषि को दोगुना आवंटनः** कृषि क्षेत्र और किसानों के कल्याण की राशि को 15,809 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 35,984 करोड़ रुपये कर दिया गया है। सिंचाई के लिए 20,000 करोड़ रुपये की लंबी अवधि का फंड तैयार किया गया है। उम्मीद है कि अगले पांच साल में किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी।

2. **स्वास्थ्य सुरक्षा योजनाः** प्रति परिवार 1 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। वरिष्ठ नागरिकों को इसके अतिरिक्त 30,000 रुपये का स्वास्थ्य बीमा मिलता है।

3. **हर बीपीएल परिवार को रसोई गैस कनेक्शनः** 2016–17 में 1.5 करोड़ बीपीएल परिवारों की महिलाओं के नाम पर रसोई गैस का कनेक्शन दिया जाएगा। तीन साल में ऐसे परिवारों की संख्या 5 करोड़ होगी।

4. **इन्फ्रास्ट्रक्चर पर सरकारी खर्चः** पिछले साल के मुकाबले इन्फ्रास्ट्रक्चर पर 22.5 फीसदी का खर्च बढ़ाकर 2.21 लाख करोड़ रुपये किया गया है। इससे 2021 की जगह 2019 तक ही 2.23 लाख किलोमीटर सड़कें बनाई जा सकेंगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में साल 2012–13 के मुकाबले खर्च दोगुना बढ़ाकर 19,000 करोड़ रुपये किया गया है।

5. **उच्च शिक्षा पर खर्चः** उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1,000 करोड़ रुपये से हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी स्थापित की गई है। इसके अलावा 10 सरकारी और 10 निजी क्षेत्र के संस्थानों को पढ़ाई और शोध में विश्वस्तरीय बनाया जा रहा है।

6. **सड़क परिवहन क्षेत्रः** गरीब और मध्यम वर्ग को राहत देने के लिए यात्री सेवा में परमिट खत्म करना, नए निवेश को बढ़ावा देना, इस क्षेत्र में उद्यमियों को प्रमोट करना और नई नौकरियों का सृजन।

7. **पब्लिसिटी यूटिलिटी (रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स) बिलः** इन्फ्रास्ट्रक्चर से जुड़े पीपीपी और पब्लिक यूटिलिटी कॉन्ट्रैक्टों में विवाद को खत्म करने के लिए बिल लाया जाना।

8. **टैक्स फ्रेंडली रेजीमः** नई विवाद निवारण योजना, जिसमें बहुत कम या शून्य

पेनाल्टी लगती है। इससे मौजूदा कर चोरी के मामलों को निपटाने में आसानी हो रही है। इसके अलावा 45 फीसदी जुर्माने के साथ काले धन की जानकारी देने के लिए समय सीमा तय की गई है।

9. **मध्यवर्गीय करदाता को राहतः** छोटे करदाता के लिए धारा 87ए में सीमा बढ़ाकर 5000 रुपये की राहत दी गई है। वहीं, मकान किराए की सीमा भी धारा 80जीजी में 60,000 रुपये की गई है।

10. **सामाजिक सुरक्षा प्लेटफॉर्मः** आधार के जरिए जरूरतमंद लोगों को सब्सिडी और अन्य वित्तीय मदद के लिए नया कानून बनाया गया है।

11. **फॉर्मल सेक्टर में रोजगार को बढ़ावाः** सभी नए कर्मचारियों के ईपीएफओ खाते में सरकार उनकी नौकरी के पहले तीन साल तक 8.33 फीसदी योगदान करेगी। इसके लिए 1000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।

12. **आसान और प्रो–मार्केट टैक्स संबंधी उपायः** कॉरपोरेट टैक्स में छूट खत्म करने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। छोटे उपकरों को खत्म किया जा रहा है। साथ ही बिना लिस्ट वाली कंपनियों को 2 साल तक लंबी अवधि का कैपिटल गेन का फायदा दिया जा रहा है।

13. **उद्यमिता को बढ़ावाः** प्रिजम्टिव टैक्स स्कीम के तहत टर्नओवर की सीमा बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये कर दी गई है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत 1.8 लाख करोड़ रुपये का कर्ज देने का लक्ष्य है। स्टार्ट अप्स के लिए 3 साल तक लाभ का 100 फीसदी छूट देने का फैसला किया गया है।

14. **सस्ते मकानः** छोटी परियोजनाओं में प्रॉफिट पर 100 फीसदी टैक्स छूट, जिसमें आरईआईटी और आईएनवीआईटी के डिविडेंट डिस्ट्रीब्यूशन शामिल न हों। पहली बार घर खरीदने वालों को प्रोत्साहन देते हुए 50,000 रुपये के अतिरिक्त ब्याज पर कर में छूट का फैसला।

15. **वित्तीय क्षेत्र की मजबूतीः** पब्लिक सेक्टर बैंकों को 25,000 करोड़ रुपये देने का फैसला, बैंकों को मजबूत करने का रोडमैप बनाया जाना, सरकारी जनरल इन्श्योरेंस कंपनियों की लिस्टिंग, वित्तीय फर्मों के बारे में नया कोड।

वित्तीय प्रबंधन

- वित्तीय वर्ष 2017 में वित्तीय घाटा 3.5 फीसदी के लक्ष्य पर रहा। इस दौरान भारत दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शुमार किया गया
- कुल खर्च 19,78,060 करोड़ रुपये
- दर्शायी गई कुल आय 14,44,157 करोड़ रुपये

- 13,77,022 करोड़ रुपये का राजस्व। इसके अलावा 67,134 करोड़ रुपये का गैर कर्ज कैपिटल रिसीट
- राजस्व में 14 फीसदी की बढ़त, नॉमिनल जीडीपी में 11 फीसदी की ग्रोथ रेट
- विनिवेश से 56,500 करोड़ रुपये का राजस्व हासिल होने की उम्मीद
- एफआरबीएम एक्ट की समीक्षा के लिए कमेटी का गठन कर उससे सुझाव लेना

मैक्रो–इकोनॉमिक स्थायित्व हासिल

- आंतरिक और वैश्विक स्थितियां चुनौतीपूर्ण हैं– वैश्विक विकास 3.1 फीसदी गिरा है। पूर्ववर्ती सरकार के दौर में विकास 6.3 फीसदी कम रहा था। सीपीआई मंहगाई की दर 9.4 फीसदी थी, लगातार दो साल मानसून में 13 फीसदी की कमी रही, वैश्विक व्यापार भी कम हुआ और राजनीतिक माहौल भी समर्थन में नहीं था
- तटस्थ एजेंसियों (आईएमएफ, डब्ल्यूईएफ इत्यादि) ने भारत को सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था कहा है। इन एजेंसियों ने विकास दर 7.6 फीसदी होने की भविष्यवाणी की है
- महंगाई की दर भी गिरकर 5.4 फीसदी पर आ गई है
- चालू खाते का घाटा इस साल के अंत तक जीडीपी का 1.4 फीसदी रहने का अनुमान है

विभिन्न क्षेत्रों में स्कीम और सुधार

कृपया इसके लिए बजट 2016–17 की मुख्य विशेषताओं को देखें।

मुख्य क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त आवंटन

सेक्टर (करोड़ रुपये में)	RE 2015-16	BE 2016-17	वृद्धि
कृषि एवं सिंचाई	25,988	47,912	84%
शिक्षा, स्वास्थ्य समेत सामाजिक क्षेत्र	1,39,619	1,51,581	9%
ग्रामीण विकास और पेयजल	90,185	1,01,775	13%
इन्फ्रास्ट्रक्चर और ऊर्जा	1,80,610	2,21,246	22%

विभिन्न मंत्रालयों के द्वारा कमजोर वर्गों के लिए अधिक आवंटन

वर्ग को आवंटन (करोड़ रुपए में)	RE 2015-16	BE 2016-17	वृद्धि
महिला कल्याण की योजनाएं	81,249	90,625	12%
बाल कल्याण के लिए आवंटन	64,635	65,758	2%
एससी सब प्लान	20,963	24,005	15%
एसटी सब प्लान	34,675	38,833	12%

किसानों को कैसे होगा लाभ?

- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत बहुत ही कम प्रीमियम पर पूरा बीमा
- उत्पाद को बेचने में सहायता के लिए एग्रीकल्चरल मार्केटिंग का ई–प्लेटफॉर्म
- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत सिंचाई की बेहतर सुविधाएं, लंबी अवधि का सिंचाई फंड, भूजल के संसाधनों का बेहतर प्रबंधन और ज्यादा कुएं और तालाब
- कर्ज के ब्याज की वापसी का दबाव कम करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए का आवंटन
- गांवों की सड़कों को जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को बढ़ावा
- क्या बोया जाए, इसकी जानकारी देने के लिए सॉयल हैल्थ कार्ड
- गांवों में इन्फ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी आर अरबन मिशन की शुरुआत
- बिचौलियों को हटाते हुए सरकार की ओर से सामाजिक सुरक्षा प्लेटफॉर्म के माध्यम से जरूरतमंदों को सीधे लाभ

गरीबों को कैसे होगा फायदा?

- 1 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य बीमा योजना
- हर परिवार को मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन
- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के माध्यम से युवा बनाए जाएंगे कुशल
- ईपीएफओ सहायता के जरिए सरकार नौकरी पाने में मदद कर रही है
- श्यामा प्रसाद मुखर्जी आर अरबन मिशन से गांवों में इन्फ्रास्ट्रक्चर सुधार
- सरकारी स्कूलों में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर विशेष ध्यान
- बिचौलियों को हटाते हुए सरकार की ओर से सामाजिक सुरक्षा प्लेटफॉर्म के

माध्यम से जरूरतमंदों को सीधे लाभ

- प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के जरिए सस्ती दवाइयां दी जाएंगी
- 1 मई, 2018 तक सभी गांवों में बिजली पहुंचाई जाएगी

युवाओं को कैसे होगा फायदा?

- नए नियमों और हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी की सहायता से विश्वस्तरीय विश्वविद्यालयों तक पहुंच
- सामाजिक सुरक्षा प्लेटफॉर्म के जरिए सीधे स्कॉलरशिप का लाभ
- स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट, डिग्री, अन्य एकेडमिक अवार्ड और मार्क शीट रखने के लिए डिजिटल तिजोरी सरकार ने बनाई है
- उद्यमियों के सपनों को स्टार्ट अप और स्टैंड अप इंडिया जैसी स्कीमों से लाभ पहुंचाया गया
- रोजगार सृजन के कदमों से नौकरियों की तादाद बढ़ी है
- मल्टी स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और नेशनल कॅरियर सर्विस के जरिए कौशल विकास
- बेहतर सड़क और रेल संपर्क

उद्यमियों को कैसे होगा फायदा?

- स्टार्ट अप्स के लिए शुरुआती तीन साल तक लाभ में 100 फीसदी छूट
- मुद्रा योजना के जरिए 1 लाख 80 हजार करोड़ का कर्ज देने का लक्ष्य
- स्टार्ट अप्स के लिए बेहतर माहौल देने हेतु कंपनीज एक्ट में बदलाव
- नई स्टार्ट अप नीति में ईको सिस्टम और नियम–शर्तें भी आसान
- प्रिजम्टिव टैक्सेशन स्कीम की धारा 44एडी के तहत टर्नओवर की सीमा बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए की गई
- प्रस्तावित दीवालिया संबंधी कानून के अंतर्गत उद्योग बंद करना आसान होगा
- जुर्माने और ब्याज की छूट संबंधी आवेदन एक साल के भीतर निपटाए जाएंगे

मध्यवर्ग को कैसे होगा फायदा?

- दालों की कीमत में स्थिरता के लिए प्राइज स्टैबलाइजेशन फंड
- होम लोन के 50,000 रुपये तक के अतिरिक्त ब्याज पर छूट। साथ ही हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में टैक्स छूट का लाभ
- डिजिटल लिट्रेसी मिशन में पंजीकरण कराकर डिजिटली साक्षर होने का मौका
- आयकर की धारा 87ए के तहत छूट की सीमा 2000 से बढ़ाकर 5000 की गई

- मकान किराए संबंधी आयकर की धारा 80 जीजी में छूट की सीमा 24,000 से बढ़ाकर प्रतिवर्ष 60,000 की गई
- सड़क परिवहन के क्षेत्र में बेहतर सुविधाएं
- नेशनल पेंशन स्कीम से 40 फीसदी धन की निकासी पर कर छूट। साथ ही नियोक्ता भी पेंशन फंड में ज्यादा योगदान दे सकता है
- आयकर रिटर्न में गड़बड़ी के समाधान के लिए ई–सहयोग योजना लागू
- जनता की स्वास्थ्य जरूरतों के मद्देनजर नेशनल डायलिसिस सर्विस प्रोग्राम
- अवैध धन जमा करने वालों से निपटने के लिए केन्द्रीय कानून ताकि वे अपनी बचत का सुरक्षित तरीके से निवेश कर सकें
- बिचौलियों को हटाते हुए सरकार की ओर से सामाजिक सुरक्षा प्लेटफॉर्म के माध्यम से जरूरतमंदों को सीधे लाभ

बाजार को कैसे होगा फायदा?

- अनलिस्टेड कंपनियों में निवेश 2 साल में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के लिए एलिजिबल होगा
- मजबूत एवं पर्याप्त रूप से कैपिटलाइज बैंकिंग सेक्टर के कारण उपयुक्त माहौल
- लिस्टेड सिक्यूरिटीज के लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में बदलाव नहीं
- स्थायी और सटीक अनुमानित टैक्स रेजीम से भारत पर भरोसा बढ़ा
- मजबूत कॉरपोरेट बॉन्ड मार्केट और बेहतर इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म
- सीमा और उत्पाद शुल्क में बदलाव से मेक इन इंडिया को बढ़ावा
- विवाद निपटान योजना के तहत टैक्स संबंधी मामलों का आसान समाधान
- जनरल इन्श्योरेंस कंपनियां स्टॉक एक्सचेंजों में लिस्टेड हो सकेंगी
- सिक्यूरिटाइजेशन ट्रस्ट के जरिए फायदा
- ऐसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज में 100 फीसदी एफडीआई को पूर्णतया मंजूरी

Steps taken by the Ministry of Agriculture and Farmers' Welfare during Modi Government for the welfare of the farmers

1. PRADHAN MANTRI FASAL BIMA YOJANA:

- With the initiatives of the Hon'ble Prime Minister, short-comings in the Crop Insurance Scheme have been removed and a new scheme – Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana has been approved for implementation across the country.
- This is the biggest financial support till date by the Central Government in Crop Insurance.
- Farmers will now have to pay the lowest premium till date for availing Crop Insurance.
- The balance premium burden will be borne by the Government - even if it is more than 90% of the total premium.
- For food-grains, pulses and oilseeds, there will be one season– one rate for the farmer. Different rates for different crops for different districts has been removed. For Kharif: maximum 2% and for Rabi: maximum 1.5% premium is to be paid by farmers.
- Farmers will get full financial security – there will be no capping on the premium rates and no reduction in the sum insured.
- In case farmer is unable to sow/transplant due to bad weather, he would be entitled to get claims.
- For the first time, risk of post harvest losses upto 14 days occurring due to cyclone, unseasonal rainfall and local calamities such as hailstorm, landslide & inundation have been included for coverage across the country.
- For the first time, mobile and satellite technology will be used for correct estimation and quick payment of claims to farmers.
- Under this scheme, provisions have been made for creation of mass awareness and publicity through media so that the number of insured farmers can be increased from present 20% to 50% in the next 2-3 years.
- An allocation of Rs. 5500 cr in the 2016-17 budget has been made under Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana which was Rs. 3185 crore in previous budget. This is an increase of about 73 % in this scheme.

मोदी सरकार के दौरान कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसानों के लिए उठाए गए कदम

1. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनाः

- माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयास से बीमा योजनाओं की विसंगतियों को दूर कर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना देश भर में लागू की गई है।
- **फसल बीमा में यह सरकार की अब तक की सबसे बड़ी मदद है।**
- खाद्यान्न, दलहन, तिलहन फसलों के लिए **एक मौसम, एक दर** होगी– जिलेवार और फसलवार अलग–अलग दर से अब मुक्ति मिलेगी

  – खरीफः सिर्फ 2% – रबीः सिर्फ 1.5%
- फलस्वरूप किसानों के लिए यह अब तक की **सबसे कम प्रीमियम दर** होगी।
- शेष भार सरकार द्वारा वहन किया जाएगा– 90% से ज्यादा होने पर भी।
- **पूरा संरक्षण मिलेगा**– बीमा पर कोई कैंपिंग नहीं होगी और इसके कारण दावा राशि में कमी या कटौती भी नहीं होगी।
- यदि खराब मौसम के कारण किसान बुआई/रोपाई नहीं कर पाते हैं, तब भी वे बीमे के दावे के हकदार होंगे।
- पहली बार देश भर में फसल कटाई के बाद 14 दिन तक चक्रवात, बेमौसम बारिश एवं स्थानीय आपदा जैसे ओले, जमीन धंसने व जल भराव से होने वाले नुकसान को भी शामिल किया गया है।
- पहली बार सही आकलन और शीघ्र भुगतान के लिए मोबाइल और सैटेलाइट टेक्नालॉजी के व्यापक उपयोग पर जोर दिया गया है।
- इस योजना का मीडिया के जरिये व्यापक जागरूकता व प्रचार प्रसार करने का बड़े पैमाने पर प्रावधान किया गया है, जिससे वर्तमान में 20% बीमित किसानों की संख्या अगले 2–3 वर्षों में बढ़ाकर 50% की जा सके।
- 2016–17 के बजट में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत आबंटन 5,500 करोड़ रुपये किया गया है जो पिछले बजट में 3185 करोड़ रुपये थे। इस प्रकार इस मद में लगभग 73 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।

2. CHANGE IN THE NORMS FOR PROVIDING RELIEF IN CASE OF DISASTER :

- To provide relief to the distressed farmers in case of disasters, Modi Government has revised the norms for providing relief. Earlier, the relief was to be given only when the damage to the crop due to disaster was 50% or more. Now this relief is being given in case of 33% damage to the crop. The amount of compensation under various heads has also been increased by 50%.
- A historical decision has been taken, whereby for foodgrains damaged due to excessive rainfall, full minimum support price will be paid. While the families of the deceased persons were given a compensation of only Rs. 1.50 lakh as per the earlier norms, Modi Government has increased the same to Rs. 4 lakh.
- For the years 2010-2015, a provision of Rs. 33580.93 crore was made for State Disaster Response Fund. The same has been increased to Rs. 61219 crore for the period 2015-2020.
- Similarly, UPA Government during the four years 2010-11, 2011-12, 2012-13 & 2013-14 approved a relief of only Rs. 12516.20 crore as against Rs. 92043.49 crore demanded by the States affected by drought and hailstorm. The Modi Government in year 2014-15 alone approved an amount of Rs. 9017.998 crore as relief to the States affected by drought and hailstorm as against their demand of Rs. 42021.71 crore. During the year 2015-16, Rs. 12781.35 crore have already been approved for till now as against a demand of Rs. 41722.42 crore.
- Under NDRF, there was no separate scheme for providing assistance to Union Territories (UTs). Keeping this in mind, Modi Government has during 2015-16 made an allocation of Rs. 50 crore for UTs.

2. आपदा राहत के मानकों में परिवर्तनः

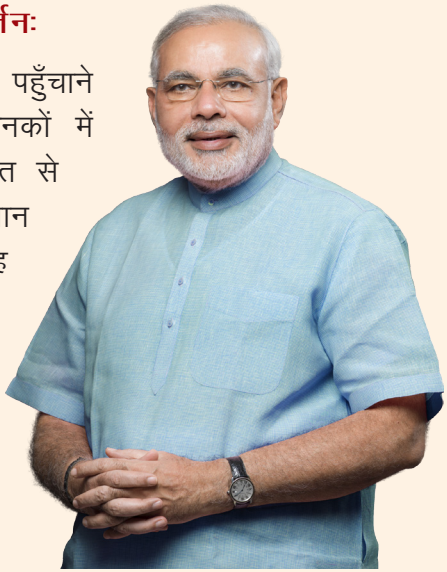

- आपदा से पीड़ित किसानों को राहत पहुँचाने के मामले में मोदी सरकार ने मानकों में परिवर्तन किया है, पहले 50 प्रतिशत से अधिक फसल का आपदा से नुकसान होने पर जो मुआवजा मिलता था वह अब 33 प्रतिशत पर प्राप्त होगा। भुगतान की राशि को भी डेढ़ गुना कर दिया गया है।
- अतिवृष्टि से खराब हुए टूटे और कम गुणवत्ता वाले अनाज का भी पूरा समर्थन मूल्य देने का ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। प्राकृतिक आपदाओं में मृतकों को पहले जहां मात्र 1.50 लाख रुपये देने का प्रावधान था, उसे मोदी सरकार ने बढ़ाकर 4 लाख रुपये कर दिया है।
- वर्ष 2010–2015 के लिए राज्य आपदा राहत कोष में 33580.93 करोड़ रुपये स्वीकृत किए थे, जबकि वर्ष 2015–2020 के लिए ये राशि बढ़ाकर 61,219 करोड़ रुपये कर दी है।
- इसी प्रकार सूखा एवं ओलावृष्टि से प्रभावित राज्यों को यूपीए सरकार के कार्यकाल के दौरान चार वर्षों 2010–11, 2011–12, 2012–13, 2013–14 में एनडीआरएफ से जहां राज्यों द्वारा रु. 92043.49 करोड़ की सहायता राशि की मांग की गई, वहां रु. 12516.20 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई। वहीं एनडीए सरकार द्वारा मात्र एक वर्ष 2014–15 में राज्यों द्वारा मांगे गए रु. 42021.71 करोड़ के सापेक्ष रु. 9017.998 करोड़ स्वीकृत किए गए। वर्ष 2015–16 में राज्यों द्वारा रु. 41722.42 करोड़ की मांग के सापेक्ष अब तक रु. 12773.34 करोड़ स्वीकृत किए जा चुके हैं।
- एनडीआएफ के तहत केंद्र शासित राज्यों के लिए सहायता की कोई योजना नहीं थी। इसे देखते हुए मोदी सरकार ने 2015–16 में केन्द्र शासित आपदा राहत कोष (यूटीडीआएफ) के लिए रु. 50 करोड़ का आवंटन किया।

3. PRADHAN MANTRI KRISHI SINCHAYEE YOJANA (PMKSY):

- With the objective of developing a long term solution for mitigating the effect of drought, PMKSY has been launched. This programme is being implemented jointly by three ministries.
- This scheme is to be implemented in mission mode. 28.5 lakh hectare area will be brought under irrigation for which a sum of Rs. 5717 crore has been earmarked for the year 2016-2017. The Ministry of Agriculture and Farmers Welfare has obtained Rs. 2340 crore in place of Rs. 1550 crore as compared to the year 2015-2016 and this is an enhancement of 51%. This amount will be used for micro irrigation (drip and sprinkler), drought proofing and water conservation activities.
- Besides this year through NABARD it has been decided to create a fund of Rs. 20,000 crore for irrigation and expeditious implementation.
- During the year 2016-17, a sum of Rs. 12517 crore will be incurred to implement 23 irrigation schemes.
- Under MNREGA, 5 lakh farm ponds and wells will be instituted in rain fed areas.
- This programme has been started with the objective of making irrigation water available to every farmer and every farm.
- 153 Officers have been trained for developing district irrigation plans. Training programme is still going on.
- Template for DIPs developed and shared with states for bringing in uniformity in planning process.
- It is targeted that 150 district irrigation plans would be prepared by 31st March, 2016.
- The district irrigation plans of all the remaining districts would be prepared by 30th September, 2016.
- Rs. 65.40 cr released to all districts of States/UTs for preparing DIPs for the year 2015-16.
- Website of PMKSY with static features launched.
- NRSC launched a page on PMKSY on BHUVAN platform integrating all relevant layers.
- There has been 40% enhancement in the provision for water management component (per drop, more crop) in 2015-16, compared to that of 2014-15. This amount will be specifically focused for micro irrigation and water conservation activities.

3. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनाः

- सूखे की समस्या से स्थायी निजात पाने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के क्रियान्वयन में तीन मंत्रालय सम्मिलित हैं।
- इस योजना को मिशन मोड में लागू किया जाना है। सिंचाई के अधीन 28.5 लाख हैक्टेयर क्षेत्र लाया जाएगा जिसके लिए नए बजट में 2016–17 के लिए 5717 करोड़ रुपये का आवंटन है, जिसमें कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय को 2015–16 की तुलना में 1550 करोड़ रुपये के बदले 2340 करोड़ रुपये है जो 51 प्रतिशत की वृद्धि है। इससे सूक्ष्म सिंचाई (ड्रिप और स्प्रिंकलर) तथा सूखा प्रूफिंग और जल संरक्षण के कार्य किए जाएंगे।
- इसके अतिरिक्त इस वर्ष नाबार्ड के माध्यम से लगभग 20,000 करोड़ रुपये का सिंचाई फण्ड सृजित करने का फैसला किया गया है।
- देश में बरसात से लम्बित 89 परियोजनाओं में से वर्ष 2016–17 के लिए 12517 करोड़ रुपये के माध्यम से 23 योजनाएं पूरी की जाएंगी।
- मनरेगा के तहत वर्षा पोषित क्षेत्रों में 5 लाख फार्म तालाबों और कुओं की व्यवस्था होगी।
- प्रत्येक किसान के खेत को सिंचाई का पानी पहुँचाने के उद्देश्य से यह योजना प्रारंभ की गई है।
- सभी जनपदों के लिए जिला सिंचाई योजना तैयार करने के लिए 153 अधिकारियों को प्रशिक्षण दे दिया गया है। प्रशिक्षण कार्यक्रम अभी भी जारी है।
- जिला सिंचाई योजना में एकरुपता लाने के लिए टैंपलेट विकसित एवं राज्यों के साथ इसे साझा किया।
- 31 मार्च, 2016 तक 150 जनपदों की जिला सिंचाई योजनाएं तैयार कर ली जाएंगी।
- 30 सितम्बर, 2016 तक समस्त जनपदों की जिला सिंचाई योजनाओं को तैयार कर लिया जाएगा।
- वर्ष 2015–16 में जिला सिंचाई योजना तैयार करने के लिए विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सभी जिलों के लिए 65 करोड़ 40 लाख रुपये की राशि राज्यों को दी गयी है।
- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की वेबसाइट स्थायी सुविधाओं के साथ लांच।
- नेशनल रिमोट सेसिंग संवेदन केन्द्र (एनआरएससी) के द्वारा सभी प्रासंगिक पहलुओं को एकीकृत करते हुए मौजूदा "भुवन" प्लेटफार्म में इस योजना पर एक पृष्ठ शुरू।

4. SOIL HEALTH CARD SCHEME :

- Soil Health Card Scheme has been taken up for the first time by Modi Government to provide information to farmers on fertility status of their soil. Earlier some of the States were implementing this scheme at their own level in different ways. There was no uniformity in sample collection, testing and fertilizer recommendation through soil health cards. Money also was not separately given to states earlier.
- Under this scheme, soil health card will be provided to all farmers of the country at an interval of two years. It will indicate appropriate recommendation of nutrients dosages to be used for crop production and will enable the farmers to improve their soil health and its fertility.
- Under this scheme a sum of 368 crore rupees has been allocated for the year 2016-17 as compared to 142 crore rupees in the year 2015-2016 which is an increase of 155%.
- 2000 model retail outlets of fertilizers companies will be opened in the forthcoming three years for soil testing and fertilizer recommendation.
- During the current year 2015-16, about 86 samples have been collected up to 15th March, 2016. During 2015-16 against the target of 500 lakh cards, about 130 lakh cards have been distributed to the farmers, 170 lakh cards are being printed by State Governments and samples are being tested for 130 lakh cards. In this way about 300 lakh cards will be distributed soon. Remaining 14 lakh samples are being collected from which 70 lakh cards will be generated. Efforts are being made to distribute 500 lakh cards to farmers by March, 2016.

4. सॉयल हैल्थ कार्ड स्कीमः

- किसान को उसकी जमीन की उर्वरक क्षमता की जानकारी देने के लिए मोदी सरकार ने देश में पहली बार सॉयल हैल्थ कार्ड स्कीम शुरू की है। इससे पहले कुछ राज्य अपने स्तर पर यह स्कीम अलग–अलग तरीके से चला रहे थे। नमूने एकत्रित करने, उनका विश्लेषण करने और सॉयल हैल्थ कार्ड द्वारा उर्वरक सिफारिशों में कोई एक समानता (Uniformity) नहीं थी। सॉयल हैल्थ कार्ड के लिए अलग से राज्यों को राशि भी नहीं दी जाती थी।
- इस स्कीम के अंतर्गत 2 वर्षों के अंतराल में देश के सभी किसानों को सॉयल हैल्थ कार्ड उपलब्ध कराया जायेगा जिससे कि फसल उत्पादन के लिए उपयुक्ता संस्तुत (Recommended) पोषक तत्वों की मात्रा का प्रयोग करने और सॉयल हैल्थ और उसकी उर्वरता में सुधार के लिए किसानों को समर्थ बनाया जा सके।
- इस स्कीम को वर्ष 2015–16 में 142 करोड़ रुपये की तुलना में वर्ष 2016–17 के लिए कुल 368 करोड़ रुपये आवंटित किये गये है, यह 155 प्रतिशत की वृद्धि है।
- साथ ही उर्वरक कम्पनियों के 2 हजार मॉडल खुदरा केन्द्रों को अगले 3 वर्ष में मृदा और बीज परीक्षण सुविधाएँ मुहैया करायी जायेंगी।
- 15 मार्च, 2016 तक वर्तमान वर्ष 2015–16 में 86 लाख नमूने एकत्रित किये जा चुके हैं। 2015–16 के 5 करोड़ कार्ड के लक्ष्य की तुलना में लगभग 130 लाख कार्ड किसानों को वितरित किए जा चुके हैं, 170 लाख कार्ड राज्य सरकारों द्वारा प्रिंट किये जा रहे हैं एवं 130 लाख कार्ड के लिए नमूनों की जांच की जा रही है। इस तरह कुल 300 लाख कार्ड वितरित हो जाएंगे। बाकी 14 लाख नमूने एकत्रित किए जा रहे हैं, जिससे शेष 70 लाख कार्ड बनाए जाएंगे। इस तरह मार्च, 2016 तक 5 करोड़ कार्ड किसानों को वितरित किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

5. PARAMPARAGAT KRISHI VIKAS YOJANA:

- First time, Modi Government has launched Paramparagat Krishi Vikas Yojana to promote organic farming. During 2016-17, an allocation of Rs. 297 cr has been made by the Central Government and it has been increased 19% from the allocation of Rs. 250 cr for the year 2015-16.
- Organic value chain for North Eastern States a sum of rupees 400 crore has been allocated in 2015-2016 for the forthcoming three years meant for the development of North Eastern States and organic value chains. This scheme has been initiated with the allocation of rupees 125 crore in 2015-2016 which will pave the way for the growth of Organic Agriculture Scheme. The remaining Rs. 275 crore will meet the needs of the projects being conducted in the next year (2016-17 and 2017-18). Alongwith 10 lakh compost ditches will be prepared for organic manure under MNREGA.

6. NEEM COATED UREA:

- Neem coated urea for improving Soil productivity
- Now, only Neem coated urea will be available in the country
- The benefit of this is that instead of 100 kg urea only 90 kg is enough
- This decision has also been taken to stop misuse of urea

5. परंपरागत कृषि विकास योजनाः

- जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार ने पहली बार परंपरागत कृषि विकास योजना को आरंभ किया गया। वर्ष 2016–17 में 297 करोड़ रुपये की केंद्र सरकार के कुल आवंटन के साथ व्यापक जैविक कृषि स्कीम है जो वर्ष 2015–16 के आवंटन 250 करोड़ रुपये के आवंटन से 19 प्रतिशत बढ़ी है। अभी तक लगभग 8000 क्लस्टर भी बना लिए गये हैं।
- उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए जैविक मूल्य श्रृंखला विकास हेतु तीन वर्षों के लिए 400 करोड़ रुपये का आवंटन वर्ष 2015–16 में हुआ, यह 125 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ वर्ष 2015–16 में शुरू की गयी। जैविक खेती की योजना को आगे बढाने में सहायता करेगा। शेष 275 करोड़ रुपये अगले वर्ष (2016–17 एवं 2017–18) की परियोजना की आवश्यकता को पूरा करेगी। साथ ही मनरेगा के तहत जैविक खाद के उत्पादन के लिए 10 लाख कम्पोस्ट गड्ढ़ों का निर्माण किया जाएगा।

6. नीम लेपित यूरियाः

- नीम कोटेड यूरियाः मिट्टी की उत्पादकता बढ़ाने के लिए
- अब देश में नीम कोटेड यूरिया ही मिलेगा
- इससे लाभ यह है कि 100 किलो की जगह यूरिया का उपयोग 90 किलो ही करना पड़ेगा
- यह निर्णय यूरिया के गलत उपयोग को रोकने के लिए भी लिया गया है

7. NATIONAL AGRICULTURE MARKET:

- In order that farmers produce may fetch the best prices, Government of India has launched the National Agriculture Market Scheme on 1st July 2015 with Rs. 200 crores, with the aim to integrate 585 regulated markets with the common e-market platform by March 2018.
- 15 States (Andhra Pradesh, Chhattisgarh, Gujarat, Jharkhand, Haryana, Himachal Pradesh, Karnataka, Rajasthan, Sikkim, Goa, Madhya Pradesh, Mizoram, Telangana, Uttarakhand and Uttar Pradesh) in the country have amended their marketing laws to include the provision for e – trading.
- 17 States and Union Territories (Andhra Pradesh, Chhatisgarh, Gujarat, Jharkhand, Himachal Pradesh, Karnataka, Rajasthan, Sikkim, Goa, Madhya Pradesh, Mizoram, Telangana, Uttarakhand, Nagaland, Punjab, Uttar Pradesh and Union Territory Chandigarh) have included the provision single point levy of market fee in their APMC Acts.
- Apart from above, 15 states (Andhra Pradesh, Chhattisgarh, Gujarat, Uttar Pradesh, Haryana, Himachal Pradesh, Karnataka, Rajasthan, Maharashtra, Sikkim, Goa, Madhya Pradesh, Mizoram, Telangana and Nagaland) have made provision of single unified licence to validate trading across the entire states.
- By 16th March, 2016 approval had been granted for a total of Rs. 159.43 crore towards integration of 365 Markets of 12 States namely Gujarat, Maharashtra, Telangana, Jharkhand, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Rajasthan, Chandigarh (UT), Uttar Pradesh, Haryana, Andhra Pradesh and Himachal Pradesh with National Agriculture Market (NAM) and for implementation of the NAM Platform by the Strategic Partner.
- Under this Scheme, the e-trading platform will be operationalized on 14th April, 2016 on the hundredth birth anniversary of Dr Bhim Rao Ambedkar.
- Between April 2016 - September 2016, 200 markets will be integrated with this e-trading Portal.
- By 31st March 2017, the next batch of 200 Mandis will be integrated with this e-trading Portal.
- Remaining 185 Mandis will be integrated with this e-trading Portal by 31st March 2018.

7. राष्ट्रीय कृषि बाजारः

- किसानों को उपज का सही मूल्य दिलाने हेतु मोदी सरकार ने 200 करोड़ रुपये की लागत से मार्च 2018 तक सामान्य ई–मार्केट प्लेटफार्म शुरू करने के उद्देश्य से 585 नियंत्रित मंडियों के साथ 1 जुलाई, 2015 से 'राष्ट्रीय कृषि बाजार' स्कीम की शुरुआत की है।
- देश में 15 प्रदेशों (आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखण्ड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, सिक्किम, गोवा, मध्य प्रदेश, मिजोरम, तेलंगाना, उत्तराखण्ड व उत्तर प्रदेश) ने अपने विपणन कानूनों में सुधार करते हुए ई–ट्रेडिंग का प्रावधान कर दिया है।
- 17 राज्य सरकारों/केन्द्र शासित क्षेत्रों (आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखण्ड, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, सिक्किम, गोवा, मध्य प्रदेश, मिजोरम, तेलंगाना, उत्तराखण्ड, नागालैंड, पंजाब, उत्तर प्रदेश व केन्द्र शासित क्षेत्र चंडीगढ़) ने अपने APMC Act में एकल बिंदु पर मंडी शुल्कों की उगाही (single point levy of market fee) की व्यवस्था का प्रावधान कर दिया है।
- उक्त के अतिरिक्त 15 राज्यों (आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, महाराष्ट्र, सिक्किम, गोवा, मध्य प्रदेश, मिजोरम, तेलंगाना व नागालैंड) ने पूरे राज्य में व्यापार करने की वैधता हेतु सिंगल यूनिफाइड लाइसेंस का प्रावधान कर दिया है।
- 16 फरवरी, 2016 तक 12 राज्य क्रमशः गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, चण्डीगढ़, उत्तर प्रदेश, हरियाणा आंध्र प्रदेश एवं हिमाचल प्रदेश की 365 मंडियों के लिए रु. 159.43 करोड़ की स्वीकृति दी जा चुकी है।
- इस स्कीम के तहत 14 अप्रैल, 2016 को डॉ. भीम राव अम्बेडकर जी के जन्म शताब्दी वर्ष पर ई–ट्रैडिंग प्लैटफार्म को लॉन्च कर दिया जाएगा।
- अप्रैल, 2016 से सितंबर, 2016 के मध्य 200 मंडियों को इस ई–ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर से उपयोग के लिए जोड़ दिया जाएगा।
- अक्टूबर, 2016 से 31 मार्च, 2017 के मध्य अगली 200 मंडियों को इस ई–ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर से उपयोग के लिए जोड़ दिया जाएगा।
- 31 मार्च, 2018 तक शेष 185 मंडियों को इस ई–ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर से उपयोग के लिए जोड़ दिया जाएगा।

8. NATIONAL FOOD SECURITY MISSION (NFSM):

- Till 2013-14 only three crops were covered under National Food Security Mission namely – Rice, Wheat & Pulses. The coverage during Modi Government has been increased to seven crops namely– Rice, Wheat, Pulses, Jute, Sugarcane, Cotton & Coarse Cereals.
- Till 2013-14 only 16 States and 468 districts were covered under NFSM. During Modi Government, all the 29 States and all 638 districts have been covered under NFSM.
- Pulses cultivation under NFSM has been taken up in J&K, Himachal Pradesh, Uttarakhand and all North Eastern States.
- Budgetary allocation for National Food Security Mission as against Rs. 1137 cr in 2015-16, Rs. 1700 cr has been allocated in the current year. It is an increase of 50% and Rs. 500 cr. has been provided for pulses.

9. DEVELOPMENT OF BEEKEEPING:

- Approved an amount of Rs. 10.43 crores to National Bee Board (NBB) during last two years(2014-15 & 2015-16) in comparison to an amount of Rs. 5.94 crores during last three years (2011-12 to 2013-14);
- 9434 farmers/ beekeepers have been trained in scientific beekeeping;
- 5634 beekeepers/ beekeeping & honey societies/ firms/ companies etc. have been registered;
- Honey production increased from 72,300 MTs in 2012-13, 76, 150 MTs in 2013-14 & 80,530 MTs in 2014-15 to 86,500 MTs in 2015-16 (estimates).

10. FINANCING OF JOINT LIABILITY GROUPS (JLGS):

- Financing of 7.28 lakh Joint Liability Groups from April 2014 to February, 2016 in just 20 months of Modi Government as compared to 6.72 lakh JLGs from April 2004 to March 2014 during the 9 years of previous government.
- In comparison to cumulative achievement of Rs. 6,775 cr. from April 2005 to March, 2014 during 9 years of previous Govt., Rs. 7084 cr. were made available to JLGs between April 2014 and February, 2016 during just 20 months of Modi Government.

8. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम):

- वर्ष 2013–14 तक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत केवल तीन फसलें– चावल, गेंहू, दलहन शामिल थी। मोदी सरकार द्वारा इस मिशन के अंतर्गत सात फसलें– चावल, गेंहू, दलहन, जूट, गन्ना, कपास व मोटे अनाज शामिल किये जा चुके हैं।
- वर्ष 2013–14 तक एनएफएसएम के अंतर्गत 16 राज्य व 468 जिले सम्मिलित थे। मोदी सरकार के दौरान अब सभी 29 राज्यों व सभी 638 जिलों को सम्मिलित किया गया हैं।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत दलहन की खेती जम्मू–कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सभी उत्तर पूर्वी राज्यों में शुरु की गयी है।
- वर्ष 2015–16 में 1137 करोड़ रुपये के मुकाबले चालू वर्ष 2016–17 में 1700 करोड़ रुपये का आवंटन है। यह वर्ष के लिए 50 प्रतिशत बढ़ी है एवं दलहन के लिए 500 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है।

9. मधुमक्खी विकास के लिए:

- एनबीबी को मधुमक्खी पालन विकास के लिए पिछले तीन वर्षों में कुल 5.94 करोड़ रुपये (2011–12 से 2013–14) की वित्तीय सहायता के एवज में पिछले दो वर्षों (2014–15 और 2015–16) में कुल 10.42 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता मंजूर की गयी।
- 9434 किसानों/मधुमक्खीपालकों को वैज्ञानिक मधुमक्खीपालन में प्रशिक्षित किया गया।
- 5639 मधुमक्खीपालकों/मधुमक्खीपालन और शहद समितियों/फर्मों कंपनियों आदि का पंजीकरण किया गया है।
- शहद उत्पादन 72,300 मीट्रिक टन (2012–13), 76,150 मीट्रिक टन (2013–14) व 80,530 मीट्रिक टन (2014–15) से बढ़कर 2015–16 में 86,500 मीट्रिक टन अनुमानित किया गया है।

10. ज्वाइंट लाएबिलिटी ग्रुप को वित्तीय सहायता:

- पिछली सरकार में अप्रैल 2005 से मार्च 2014 तक 9 वर्षों में 6.72 लाख ज्वाइंट लाएबिलिटी समूहों की तुलना में मोदी सरकार द्वारा अप्रैल 2014 से फरवरी 2016 तक केवल 20 माह में 7.28 लाख समूहों को वित्तीय सहायता प्रदान की गयी।
- अप्रैल 2005 से मार्च 2014 तक 9 वर्षों में रु. 6775 करोड़ की संचित उपलब्धियों की तुलना में मोदी सरकार द्वारा अप्रैल 2014 से फरवरी 2016 तक 20 माह में रु. 7084 करोड़ की राशि की वित्तीय सहायता संयुक्त देय समूहों को प्रदान की गयी।

11. ANIMAL HUSBANDRY, DAIRYING & VETERINARY EDUCATION:

- Rashtriya Gokul Mission, a new initiative under National Programme for Bovine Breeding and Dairy Development has been launched for the first time in the country, with a view to conserve and develop indigenous bovine breeds.
- Since 2007-08 to 2013-14, a meagre amount of only Rs 45 crore was spent for the development of indigenous breeds. Whereas, the current Government has in only one and a half years, upto December 2015, has approved 29 projects from 27 States and has sanctioned Rs 550 crore.
- Two National Kamdhenu Breeding Centre, one in northern region and other in southern region are being established in the country with an allocation of Rs 50 crores.
- India is number one in milk production in the world. Milk production has increased from 137.61 million tonnes during 2013-14 to 146.31 million tones and 160 million tones (projected) during 2014-15. During past 10 years, world milk production on an average increased by 2.2% annually while in India milk production has increased by 4.2% annually. During 2014-15 and 2015-16, milk production in the country has increased by 6.3% and 9% (projected) respectively.
- In order to meet the shortage of trained veterinary manpower, the number of veterinary colleges has increased from 36 to 46. Intake of students in various Veterinary Colleges was enhanced from 60 to upto 100 seats. Total number of seats has been increased to 1,332 from 914 in 17 Veterinary Colleges. The number of veterinary graduates has increased by one and half times. Similarly the seats in veterinary colleges have increased by one and half times. One and a half time increase in post graduate studies in veterinary education has been attained. Seats in veterinary colleges have been increased by one and a half time.
- **Four New Projects –** Rs. 850 crore have been provided for in the new budget, Livestock Sanjivani, Nakul Swasthan Patra, e-livestock haat and Rastriya Indiginous Breeds Genomic Centre.
- An amount of Rs. 1600 crore has been allocated for Animal Husbandry, Diary and Fisheries for 2016-17 which was Rs. 1491 crore in 2015-16.
- **During the year 2014-15, 78,484 million eggs were produced in the country against 74752 million eggs produced during 2013-14. Egg production is now increasing 5% annually.**

11. पशुपालन डेयरी – चिकित्सा शिक्षाः

- देश में पहली बार राष्ट्रीय बोवाईन प्रजनन एवं डेयरी विकास कार्यक्रम के तहत देशी नस्लों के संरक्षण और संवर्धन के लिए एक नई पहल 'राष्ट्रीय गोकुल मिशन' को प्रारम्भ किया गया है।
- देसी नस्लों के विकास के लिए 2007–08 से 2013–14 तक केवल रु. 45 करोड़ इस कार्य के लिए खर्च किए गए थे, जबकि वर्तमान सरकार द्वारा दिसंबर 2015 तक केवल डेढ़ वर्षों में 27 राज्यों से आए 29 प्रस्तावों के लिए रु. 550 करोड़ स्वीकृत किए जा चुके हैं।
- दो नए **राष्ट्रीय कामधेनु ब्रीडिंग सेंटर** (एक उत्तर भारत और एक दक्षिण भारत में) भी स्थापित किए जा रहे हैं जिसके लिए रु. 50 करोड़ आवंटित किए गए हैं।
- देश दुग्ध उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर है। दुग्ध उत्पादन वर्ष 2013–14 में 137.61 मिलियन टन से वर्ष 2014–15 में 146.31 मिलियन टन हो गया व 2015–16 में 160 मिलियन टन अनुमानित है। विश्व में दुग्ध उत्पादन 10 वर्षों का औसत वृद्धि दर 2.2 प्रतिशत है, जबकि भारत का औसत वृद्धि दर 4.2 प्रतिशत है। वर्ष 2014–15 व 2015–16 के दौरान दुग्ध उत्पादन की वार्षिक वृद्धि दर 6.3 प्रतिशत व 9 प्रतिशत (अनुमानित) है।
- पशु चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षित पशु चिकित्सों की कमी को पूरा करने के लिए विभिन्न पशु चिकित्सा कॉलेजों की संख्या 36 से बढ़ाकर 46 की गई है तथा कॉलेजों में भर्ती होने वाले विद्यार्थियों की संख्या को 60 से बढ़ाकर 100 तक किया गया था। 17 पशु चिकित्सा कॉलेजों में सीटों की कुल संख्या को 914 से बढ़ाकर 1,332 किया गया है। **पशु चिकित्सा स्नात्तकोत्तर में डेढ़ गुना की वृद्धि हासिल की गयी। पशु चिकित्सा विद्यालय में भी डेढ़ गुना सीटें बढ़ायी गयीं।**
- **अलग से चार नई परियोजनाएं** – नए बजट में 'पशुधन संजीवनी' 'नकुल स्वास्थ्य पत्र', ई–पशुधन हाट और राष्ट्रीय देशी नस्ल जेनोमिक केन्द्र के लिए 850 करोड़ रुपये दिए गए हैं।
- पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्यपालन के लिए वर्ष 2016–17 में 1600 करोड़ रुपये आवंटित किए गए, जो 2015–16 में 1491 करोड़ रुपये थे।
- **वर्ष 2014–15 के दौरान 78,484 मिलियन अंडों का उत्पादन हुआ जबकि इसी दौरान 2013–14 मे 74,752 मिलियन अंडों का उत्पादन हुआ था। अंडा उत्पादन की वार्षिक वृद्धि दर 5% है।**

12. BLUE REVOLUTION:

- Realizing the immense scope for development of Fisheries, the Modi Government has heralded 'Blue Revolution' in this Sector. Accordingly, an umbrella Scheme namely 'Blue Revolution' has been formulated by merging all the ongoing schemes in this sector.
- Integrated development of entire fisheries sector has been made easy by consolidating Inland and Marine Fisheries under the 'Blue Revolution' scheme. Main focus of Blue Revolution is to increase fish production from aquaculture by introduction of advanced technologies and through utilization of vast fishery resources available in the country.
- For Blue Revolution scheme, central budget of Rs. 300 crore is earmarked for five years.
- Fish production has increased from 95.72 lakh tones during 2013-14 to 101.64 tonnes during 2014-15 (an increase of Rs.5.92 lakh tones).
- The fish production for 2015-16 is estimated at 109 lakh tones (an increase of 7.36 lakh tones).
- The amount of Rs. 600 per month being provided under 'Saving-cum-Relief' component during 2013-14 by the previous Government, has been increased by the Modi Government to Rs. 900 per month during 2014-15, and it has been further revised to Rs. 1500 per month under Blue Revolution scheme.
- Under the sector of 'Blue Revolution: Integrated Development and Management of Fisheries' central financial assistance to North Eastern States has been increased from 75 percent to 80 percent.

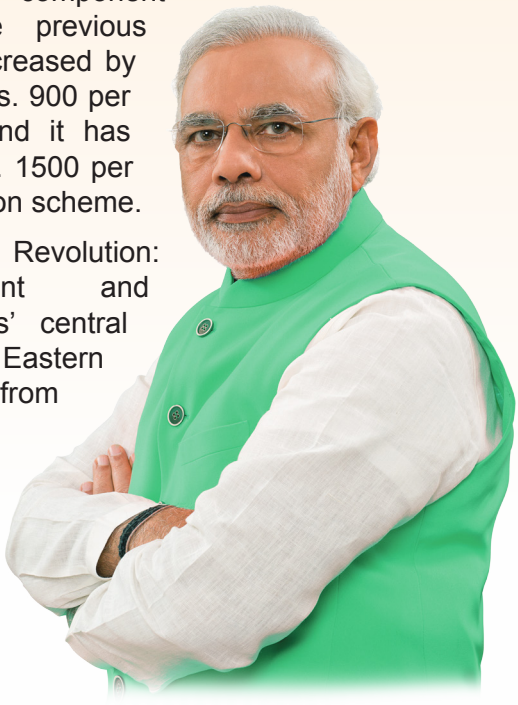

12. नीली क्रांतिः

- मात्स्यिकी में विकास की अपार संभावनाओं को देखते हुए मोदी सरकार ने मात्स्यिकी क्षेत्र में 'नीली–क्रांति' का आह्वान किया है। जिसके अनुरूप, इस क्षेत्र की सभी योजनाओं को समेकित करते हुए, एक छत्र योजना, 'नीली–क्रांति' का सृजन किया गया है।
- अंतर्देशीय व समुद्री मात्स्यिकी को 'नीली–क्रांति योजना' में समेकित करते हुये सम्पूर्ण मात्स्यिकी सेक्टर के एकीकृत विकास को सुगम बनाया गया है। 'नीली क्रांति' में विशेष रूप से जलकृषि में उन्नत तकनीकी के प्रयोग से, देश में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध जलीय–संसाधनों से मछली–उत्पादन को बढ़ाने पर ध्यान केन्द्रित है।
- 'नीली क्रांति' योजना हेतु पांच वर्षों की अवधि के लिए रु. 3000 करोड़ का केन्द्रीय बजट निर्धारित है।
- मछली–उत्पादन 2013–14 में 95.72 लाख टन से बढ़कर 2014–15 में 101.64 लाख टन (5.92 लाख टन की वृद्धि)।
- 2015–16 में अनुमानित उत्पादन 109 लाख टन (7.36 लाख टन अधिक)।
- 'बचत–सह–राहत' घटक के अंतर्गत दी जाने वाली राहत राशि जो वर्ष 2013–14 में पूर्व सरकार के दौरान रु. 600 प्रतिमाह थी, उसे मोदी सरकार ने वर्ष 2014–15 में बढ़ाकर रु. 900 प्रतिमाह किया एवं 'नीली–क्रांति' योजना के बाद इसमें अब पुनः परिवर्तन करते हुए रु. 1500 प्रतिमाह कर दिया गया है।
- नीली क्रांति पर केंद्रीय क्षेत्र की मात्स्यिकी का समन्वित विकास एवं प्रबंधन योजना के अंतर्गत उत्तर–पूर्वी राज्यों को दी जाने वाली केंद्रीय वित्तीय सहायता को 75 प्रतिशत से बढ़ाकर 80 प्रतिशत किया गया है।

13. AGRICULTURAL EDUCATION AND RESEARCH:

- Recognizing the enormous potential of North-East India, six new colleges were opened by Modi government under Central Agricultural University, Imphal. Due to this, the number of agricultural colleges in the Northeast region has increased by almost 85 percent in the last two years.
- Similarly, in the Bundelkhand region, 4 new colleges were opened under Rani Lakshmi Bai Central Agricultural University, Jhansi.
- On the lines of Pusa Research Institute, New Delhi, for the first time in 68 years, Indian Agricultural Research Institute (IARI) was established in Barhi, Jharkhand and now one more is being set up in Asom.
- To promote higher agricultural education in different states, Modi government has established eight new agricultural universities. Compared to 2013, due to the efforts of the new government, in 2015, there was nearly 41 percent increase in the intake of students in the State Agricultural Universities through ICAR.
- Rural Agricultural Work Experience (RAWE) is aimed to provide real life experience and opportunity to work with farmers and identify production, protection and marketing constraints, industrial attachment, inplant training etc. the scholarship for the work experience students has been increased from Rs. 750/- to Rs. 3000/- per month from the year 2016.
- Under the National Talent Scholarship (NTS) the financial assistance to the Under Graduates has been increased from Rs. 1000/- to Rs. 2000/- per month and a new initiative for scholarship of Rs. 3000/- per month has been taken for the Post Graduates who go for ready in other State from the year 2016.
- Compared to 2013, the number of empirical learning units in agricultural colleges increased by almost 50 percent.
- To increase the efficiency and reduce total cost of farming, a total of 9067 prototypes of new agricultural equipment were developed. As compared to 2013, the number has almost doubled.
- To accelerate the progress of second green revolution in Eastern India, second such centre "National Centre for Integrated Farming Research" is being setup in Motihari, Bihar.

13. कृषि शिक्षा एवं अनुसंधानः

- पूर्वोत्तर भारत की अपार क्षमताओं को पहचानते हुए मोदी सरकार द्वारा केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल के अंतर्गत छः नए कॉलेज खोले गये। इससे पूर्वोत्तर भारत में कृषि कॉलेजों की संख्या में पिछले दो वर्षों में लगभग 85 प्रतिशत से ज्यादा की बढ़ोत्तरी हुई।
- इसी प्रकार बुंदेलखंड क्षेत्र में रानी लक्ष्मीबाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झांसी के अंतर्गत 4 नए कॉलेज खोले गए।
- पूसा अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली की तर्ज पर 68 साल में पहली बार बरही, झारखंड में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (IARI) की स्थापना की गई एवं असम में भी स्थापना की जा रही है।
- विभिन्न राज्यों में उच्च कृषि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार ने आठ नए कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना की है। वर्ष 2013 की तुलना में नई सरकार के प्रयासों के परिणामस्वरूप वर्ष 2015 में भाकृअनुप द्वारा राज्य कृषि विश्वविद्यालयों में छात्रों के दाखिले में लगभग 41 प्रतिशत की वृद्धि की जा सकी।
- ग्रामीण कृषि कार्य अनुभव (Rural Agricultural Work Experience - RAWE) इस योजना के तहत उत्पादन, संरक्षण तथा मार्केटिंग बाधाओं की पहचान करने तथा किसानों के साथ कार्यानुभव के लिए छात्रों की स्कॉलरशिप को वर्ष 2016 से रु. 750/– से बढ़ाकर रु. 3000/– प्रतिमाह किया गया।
- राष्ट्रीय प्रतिभा स्कॉलरशिप (National Talent Scholarship) के तहत वर्ष 2016 से अंडर ग्रेजुएट छात्रों की स्कॉलरशिप को रु. 1000/– से बढ़ाकर रु. 2000/– प्रतिमाह किया गया तथा **नई पहल** करते हुए वर्ष 2016 से पीजी छात्रों (जो गृह राज्य से बाहर किसी दूसरे राज्य में जाकर पढाई करना चाहते हैं) को रु. 3000/– प्रतिमाह दिये जाने का निर्णय लिया गया है, जबकि इन्हें पहले कोई स्कॉलरशिप/वित्तीय सहायता नहीं दी जाती थी।
- वर्ष 2013 के मुकाबले कृषि कॉलेजों में अनुभवजन्य लर्निंग इकाइयों की संख्या में लगभग 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
- खेतों में कार्यकुशलता बढ़ाने तथा खेती की लागत को कम करने के लिए कुल 9,067 नए कृषि उपकरणों के प्रोटोटाइप का विकास किया गया। वर्ष 2013 के मुकाबले इनकी संख्या बढ़कर लगभग दोगुनी हो गई।
- पूर्वी भारत में दूसरी हरित क्रांति में तेजी लाने हेतु मोतिहारी (बिहार) में देश का दूसरा 'राष्ट्रीय समेकित कृषि अनुसन्धान केंद्र' की स्थापना।

- It has been decided to establish first National Organic Agricultural Research Institute in Gangtok, Sikkim.
- 79 new contingency plans developed and implemented in 600 affected districts to mitigate the effect and save the livelihood of farmers from natural calamities like drought, floods, fog, storms, etc.
- New soil testing (Mrida Parikshak) Kit developed for rapid soil testing and balance fertilizer recommendation.
- Increase in recruitment of scientists – 81 % recruitment in 2014-15 and 2015-16 in comparison to only 66% in 2013-14, accelerated recruitment process through open competition and increase in representation of women scientists.
- A total financial resources of Rs. 5387.95 crore was provided to DARE/ ICAR in the year 2015-16 whereas in the year 2016-17 financial resources of Rs. 6309.89 crore has been made available with an increase of about 17 % compared to the last year which will give impetus to education, research and agricultural extension.

- गंगटोक, सिक्किम में देश का सबसे पहला राष्ट्रीय जैविक कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना का निर्णय लिया गया है।
- वर्ष 2015 में 79 नई आकस्मिक योजनाएं बनाकर कुल 600 जिलों में इन्हें सूखा, बाढ़, ओला, पाला, तूफान जैसी प्राकृतिक आपदाओं को कम करने तथा किसानों की आजिविका सुरक्षित रखने के लिए लागू की गयीं।
- नया मृदा परिक्षक विकसित किया गया जिससे संतुलित उर्वरक संस्तुति एवं त्वरित मृदा परिक्षण संभव हुआ।
- **कृषि वैज्ञानिकों की भर्ती को बढ़ावा**– वर्ष 2013–14 में 66% भर्ती के मुकाबले 2014–15 व 2015–16 में लगातार 81% भर्ती, खुली प्रतियोगिता से भर्ती प्रक्रिया को तेज किया गया व कृषि शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ायी गयी।
- **वर्ष 2015–16 में डेयरी/भाकृअप** को 5387.95 करोड़ रुपये की कुल वित्तीय संसाधन प्रदान किए गए, जबकि वर्ष 2016–17 में इसमें पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 17 प्रतिशत वृद्धि के साथ 6309.89 करोड़ रुपये के वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराये गए। जिससे शिक्षा, अनुसंधान एवं कृषि विस्तार को गति मिलेगी।

14. NEW AND ADVANCED VARIEITIES OF PULSES, OILSEEDS AND OTHER CROPS:

- During last two years 155 new advanced varieties have been developed for different crops including cereals, oilseeds, pulses, fibers and forage crops.
- Twenty new and high yielding varieties of pulses and 24 of oilseeds have been developed during last two years having disease tolerance and resistance.
- In addition to high yield, the oil content is also on the higher side in this variety of oilseeds.
- Ninety six varieties have been developed for cereals including rice and wheat, three for fiber crops, nine for forage crops and three for sugarcane.
- A new variety 'Pusa Mustard 30' and its oil have been launched commercially on 4 February 2016. It contains negligible quantity of undesirable erucic acid which is harmful to hearth health.
- Previously cultivation of 'Khesari (Lathyrus) Dal' was banned because its consumption was injurious to human health. Three new varieties of 'Khesari Dal' have been developed having negligible quantity of harmful chemical OADP. Initiative has been taken to start cultivation of new and safe Khesari Dal varieties.

14. दलहन, तिलहन तथा अन्य फसलों की नई उन्नत किस्में:

- विगत दो वर्षों के दौरान अनाज, तिलहन, दलहन, रेशेदार फसल और चारा फसलों की 155 नई उन्नत किस्में विकसित की गईं।
- विगत दो वर्षों में दलहन की 20 तथा तिलहन की 24 अधिक उपज देने वाली तथा रोग सहिष्णु व रोगरोधी किस्में विकसित की गईं।
- तिलहन की प्रजातियों में उच्च पैदावार के अतिरिक्त, तेल की मात्रा भी अधिक है।
- धान एवं गेंहू सहित अनाजों की 96 किस्में, रेशेदार फसलों की 3, चारा फसलों की 9 तथा गन्ने की 3 किस्में विकसित की गईं।
- विगत 4 फरवरी, 2016 को सरसों की नई किस्म 'पूसा मस्टर्ड 30' तथा इसके तेल को व्यावसायिक स्तर पर जारी किया गया। इसमें हृदय स्वास्थ्य के लिए हानिकारक इरूसिक एसिड की मात्रा ना के बराबर है।
- पूर्व में हानिकारक रसायनों के कारण प्रतिबंधित खेसारी दाल की 3 नई किस्में विकसित की गईं, जिनमें हानिकारक रसायन ओएडीपी की मात्रा नगण्य है। नई व सुरक्षित खेसारी दाल किस्मों की खेती के प्रसार के लिए पहल की जा रही है।

15. KRISHI VIGYAN KENDRA:

- Efforts were made for strengthen the KVKs by enhancing the number of staff positions of KVKs from the existing strength of 16 to 22.
- The facility for Soil and Water Testing labs in 195 KVKs, Rain Water Harvesting Structures in 183 KVKs, Minimal Processing Facilities in 221 KVKs and seed processing facility on small scale in 109 KVKs will be established. Mobile soil testing kits have been provided to 400 KVKs.
- About 50 % financial assistance has been enhanced to the KVK system in 2015 as compared to 2013. 109 new KVKs including 59 KVKs in larger districts and 5KVKs in mountain districts will be established.
- Six new KVKs have been established on the initiative of the new Government. Besides these, proposals to open 49 new KVKs have been obtained from States out of which site selection has been completed for 20 KVKs.
- There were only 8 Zonal Project Directorates up to 2013 to monitor the KVKs. The new Government has increased this number to 11 and to make these Directorates more effective, these have been upgraded as Agricultural Technology Application Research Institutes. Three new institutes are being established at Patna, Guwahati & Pune.
- For the first time, under the special mission on Pulses and Oilseeds, 474 KVKs on pulses and 299 KVKs on oilseeds have demonstrated advanced technologies on farmer's field. These frontline demonstrations are being conducted in more than 60000 acres area.
- For the first time in the country, World Soil Day was organised on December 5, 2015 by 607 KVKs and 80 ICAR Institutes/ SAUs to educate the farmers about soil health and use of recommended fertilizers. On this occasion, about 2.5 lakh soil health cards were prepared and distributed to the farmers. A Soil testing kit was developed for quick analysis of soil samples to optimise the use of fertilisers. This soil testing kit has been provided to 400 KVKs.

15. कृषि विज्ञान केन्द्रः

- कृषि विज्ञान केन्द्रों को पहली बार सुदृढ़ करने का कार्य प्रारंभ किया गया जिसके तहत प्रत्येक कृषि विज्ञान केन्द्र में कार्मिकों की संख्या 16 से बढ़ाकर 22 की गई है।
- 195 केवीके में मृदा एवं जल नमूनों की जांच के लिए प्रयोगशालाएं, 183 केवीके में वर्षाजल संग्रहण ढांचा, 221 केवीके में बुनियादी प्रसंस्करण सुविधाएं एवं 109 केवीके में लघु स्तर पर बीज प्रसंस्करण सुविधा दी जाएगी। 400 केवीके पर मोबाइल मृदा परीक्षण किट उपलब्ध कराये जा चुके हैं।
- वर्ष 2013 के मुकाबले वर्ष 2015 में कृषि विज्ञान केन्द्रों के लिए बजट में लगभग 50 प्रतिशत अधिक धनराशि आवंटित की गई। 59 बड़े जिलों में तथा 5 पर्वतीय जिलों में किसानों को बेहतर सुविधा पहुंचाने हेतु दूसरा केवीके स्थापित करने का निर्णय लिया गया।
- नई सरकार की पहल पर 6 नए केवीके स्थापित किए गए। इसके अलावा 49 नए केवीके खोलने के प्रस्ताव राज्यों से प्राप्त किए गए हैं, जिसमें से 20 के लिए स्थल चयन कर लिया गया है।
- केवीके के कार्य की देखरेख के लिए वर्ष 2013 तक केवल आठ जोनल परियोजना निदेशालय ही थे। नई सरकार ने निदेशालयों की संख्या आठ से बढ़ाकर ग्यारह कर दी है और साथ ही निदेशालय को अधिक प्रभावी बनाते हुए इन्हें कृषि प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग संस्थान (अटारी) के रूप में उन्नत किया गया। तीन नए संस्थान पटना, गुवाहाटी एवं पुणे में स्थापित किए जा रहे हैं।
- पहली बार दलहन विशेष मिशन के अंतर्गत 474 केवीके द्वारा दलहनी फसलों पर तथा 299 केवीके के द्वारा तिलहनी फसलों पर उन्नत तकनीकों का प्रदर्शन किया जा रहा है। कुल मिलाकर, 60 हजार एकड़ से अधिक क्षेत्रफल में अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन किए जा रहे हैं।
- पहली बार देश भर में 5 दिसम्बर, 2015 को कुल 607 कृषि विज्ञान केन्द्रों एवं भाकृअनुप के 80 संस्थानों/राज्य कृषि विश्वविद्यालयों में विश्व मृदा दिवस का आयोजन करके किसानों को मृदा स्वास्थ्य तथा संतुलित उर्वरक उपयोग के बारे में जागरूक किया गया। इस अवसर पर कुल 2.5 लाख सॉयल हैल्थ कार्ड तैयार कर किसानों को वितरित किए गए। मिट्टी की तुरंत जांच तथा संतुलित उर्वरकों की सिफारिश के लिए पहली बार आईटी आधारित मृदा परीक्षक किट का विकास किया गया तथा 400 केवीके को यह किट दिया गया है।

- 97 MPs, 184 MLAs, 10 Union Ministers, 34 ministers from States, 1 Governor and 2 Chief Ministers participatedin the Soil health card distribution function organised by KVKs on December 5, 2015.
- Kharif Farmer Conference was organized by 330 KVKs which was attended by Hon'ble MPs and local people's representative. On this occasion, technical films were displayed by KVKs and distribution of related sites, showcase of technical products, etc. were published. 1,54,495 farmers participated in the Kharif Kisan Conference. Rabi Farmer Conference was organized by 500 KVKs during the Rabi season.
- To strengthen the interface between farmers and scientists, Jai Kisan Jai Vigyan Week was celebrated for the first time during December 23-29, 2015.
- **Mera GaonMera Gaurav** programme has been initiated to effectively promote direct interface of scientists of ICAR Institutes and State Agricultural Universities with the farmers to hasten the lab to land process. For this, a group of four scientists each will adopt 5 villages. Thus, there will be nearly 5000 groups of scientists adopting 25000 villages. At present, agricultural scientists have started providing information on newer technologies to the farmers in 15000 villages.
- A competition of national level will be organized among 643 KVKs with a total award amount of Rs. 50 lakh for bringing reforms in the efficiency and performance of the KVKs.

- कृषि विज्ञान केन्द्रों व संस्थानों पर आयोजित सॉयल हैल्थ कार्ड वितरण समारोह (5 दिसम्बर, 2015) में 97 सांसदों, 184 विधायकों, 10 केन्द्रीय मंत्रियों, राज्यों के 34 मंत्री, 1 राज्यपाल व 2 मुख्यमंत्रियों ने सहभागिता की।
- **खरीफ किसान सम्मेलन** 330 कृषि विज्ञान केंद्रों द्वारा आयोजित किया गया जिसमें माननीय सांसदगण एवं स्थानीय जन–प्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित की गई। इस अवसर पर कृषि विज्ञान केंद्रों के द्वारा तकनीकी फिल्मों को प्रदर्शित किया गया एवं संबंधित साईट्स का वितरण, तकनीकी उत्पादों का प्रदर्शन आदि को संपादित किया गया। खरीफ के द्वारा आयोजित किसान सम्मेलनों में 1,54,495 किसानों की भागीदारी सुनिश्चित की गई। रबी मौसम के दौरान 500 कृषि विज्ञान केंद्र पर **रबी किसान सम्मेलन** आयोजित किये गये हैं।
- वैज्ञानिकों का किसानों के साथ सम्पर्क बढ़ाने के लिए पहली बार, देशभर में भाकृअनुप के संस्थानों और केवीके में दिनांक 23–29 दिसम्बर, 2015 के दौरान जय किसान–जय विज्ञान सप्ताह का आयोजन किया गया।
- **मेरा गांव – मेरा गौरव** योजना को गांव तक वैज्ञानिक कृषि की प्रभावी तथा व्यापक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए कृषि विश्वविद्यालय एवं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के कृषि वैज्ञानिकों को शामिल कर प्रारंभ किया गया है। इस उद्देश्य के लिए चार–चार वैज्ञानिकों के 5,000 समूह एक वर्ष में 25,000 गांव से सम्पर्क करेंगे। अभी तक 15,000 ग्रामों में कृषि वैज्ञानिक सम्पर्क कर नयी तकनीकी जानकारी देने का कार्य कर रहे हैं।
- कृषि विज्ञान केन्द्रों की प्रभावशीलता और प्रदर्शन में सुधार लाने के लिए 50 लाख रुपये की कुल पुरस्कार राशि के साथ 643 कृषि विज्ञान केन्द्रों के बीच एक राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी।

सक्षम किसान

किसान सुरक्षा

- **प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना**

  फसल बीमा के लिए सरकार की ओर से अब तक की सबसे बड़ी सहायता किसानों के लिए सबसे कम बीमा की दर– एक फसल–एक दर (खरीफः 2 प्रतिशत, रबीः 1.5 प्रतिशत, व्यावसायिक और बागवानी फसलेंः 5 प्रतिशत)

  – **पूर्ण सुरक्षा** – दावे की राशि में कोई कमी या उच्चतम सीमा नहीं।
- **गन्ने के किसानों के लिए प्रभावी नीतिगत फैसले**– बकाया राशि रु. 21,000 करोड़ से घटकर रु. 2,500 करोड़, निर्यात शुल्क में बढ़ोत्तरी, एथेनॉल ब्लेडिंग में 250 प्रतिशत की वृद्धि।
- **प्राकृतिक आपदा राहत मानदंड** : मुआवजा डेढ़ गुना बढ़ा, पात्रता 50 प्रतिशत से घटाकर 33 प्रतिशत की गई, सरकारी खरीद में मानकों में ढ़ील, ऋण के भुगतान और समय सीमा में परिवर्तन, डीजल में सब्सिडी के साथ बीजों के लिए सब्सिडी में 50 प्रतिशत की वृद्धि।
- ऋण पहुंच को आसान बनाने के लिए कृषि ऋण प्रवाह बढ़ाकर वर्ष 2015–16 में रु. 8.50 लाख करोड़ किया गया है एवं 2016–17 के लिए रु. 9 लाख करोड़ किया गया है।
- **विश्व व्यापार संगठन** में किसानों की दीर्घकालीन हितों की सुरक्षा मोदी सरकार ने की है।

किसान शक्ति

- **प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना** : सिंचाई परियोजनाओं और जलागम विकास (हर खेत को पानी), बूंद–बूंद और छिड़काव (प्रति बूंद–अधिक फसल) सिंचाई परियोजना को लक्ष्य अनुरूप पूरा करना।
- **दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना** – कृषि और गांवों को विद्युत सुनिश्चित करने के लिए फीडर अलग करना।
- **तीन करोड़ प्रभावी पंप सेटो के वितरण की योजना** – सिंचाई सुविधाओं में सुधार और कृषि आय में बढ़ोतरी।
- **जुलाई, 2015 में राज्यों को निर्देश** – मनरेगा योजना अंतर्गत कम–से–कम 60 प्रतिशत राशि कृषि कार्यों में खर्च करना।
- **सॉयल हैल्थ कार्ड** – स्वच्छ धरा–खेत हरा, 80 लाख सॉयल हैल्थ कार्डों का वितरण, मार्च, 2017 तक सभी को वितरण करने का लक्ष्य।
- **यूरिया पर नीम की परत** – उर्वरक की क्षमता में बढ़ोतरी और अन्य प्रयोगों को रोकना।

समृद्ध भारत

- **नई उर्वरक नीति** – उर्वरकों की कमी न होने देने और पूर्ण उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए उर्वरक उत्पादन में बढ़ोतरी।
- **राज्यों के साथ संयुक्त राष्ट्रीय कृषि बाजार विकसित करना** – ई–प्लेटफार्म की स्थापना करना।
- **किसान टीवी** – किसानों को मौसम, किसान मंडी और अन्य आंकड़ों में मदद के लिए सातों दिन 24 घंटे का चैनल।

किसान उन्नति

- **परम्परागत कृषि विकास योजना** – पहली बार जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए योजना
- **नीली क्रांति** – मछली पालन में विकास दर 5.8 प्रतिशत से बढ़कर 7.25 प्रतिशत हुई।
- **श्वेत क्रांति** – दूध का उत्पादन 146 मिलियन टन से बढ़ाकर 160 मिलियन टन हुआ।
- **राष्ट्रीय गोकुल मिशन** – स्वदेशी प्रजाति को संरक्षित और विकसित करने के लिए गत 18 माह में 550 करोड़ रुपये के प्रस्तावों की मंजूरी एवं दो राष्ट्रीय कामधेनु ब्रीडिंग केन्द्रों के लिए 50 करोड़ रुपये की स्वीकृति।
- **राष्ट्रीय कृषि वानिकी कार्यक्रम** हेतु पहली बार 2016–17 के बजट में 75 करोड़ केन्द्रांश का प्रावधान किया गया है। इससे मेड पर पेड़ अभियान को गति मिलेगी।
- **अलग से चार नई परियोजनायें** – 2016–17 के नए बजट में 'पशुधन संजीवनी' 'नकुल स्वास्थ्य पत्र', ई–पशुधन हाट और राष्ट्रीय देशी नस्ल जेनोमिक केन्द्र के लिए 850 करोड़ रुपये दिए गए हैं।
- **दीनदयाल अन्त्योदय मिशन**– सूखाग्रस्त और ग्रामीण आपदा से ग्रस्त प्रत्येक ब्लॉक विशिष्ट ब्लॉक के रूप में काम करेगा। स्वयं सहायता समूह का गठन किया जाएगा। मनरेगा के तहत कलस्टर सुविधा टीमों का भी गठन किया जाएगा जो जल संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंध को सुनिश्चित करेगी। इन जिलों को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत भी प्राथमिकता दी जाएगी।
- **श्यामा प्रसाद मुखर्जी (ररबन)**– गांवों में आधारभूत संरचना के विकास के लिए शुरुआत। 300 ग्रामीण शहरी कलस्टरों का विकास किया जाएगा, जिसमें किसानों के लिए आधारभूत संरचना जैसे कृषि प्रसंस्करण, कृषि बाजार को सुलभ कराना, गोदाम एवं वेयरहाउसों को बनाना है।

EMPOWERED FARMER

FARMER SECURITY:

- **Prime Minister Fasal Bima Yojana :**

  Biggest financial support till date by the Central Government in crop insurance

  Lowest premium rate for farmers – one crop – one rate (Kharif : 2 %, Rabi: 1.5 %, Commercial and Horticulture Crops: 5 %)

  - Full Security – no capping and no reduction in the sum insured.

- **Important policy decision for sugarcane farmers –** reduction in outstanding payments from Rs. 21,000 cr to Rs. 2500 cr, increase in export duty, increase of 250 percent in ethanol blending.
- **Relief norms for natural disasters:** compensation increased by 50%, eligibility criteria reduced from 50% to 33%, flexibility in government procurement norms, change in payment and time norms of loans, diesel subsidy and 50% increase in seed subsidy.
- Financial flow in the agriculture sector has been increased to Rs. 8.50 lakh crore in 2015-16 and to Rs. 9 lakh crore in 2016-17 to improve the loan reach and accessibility.
- Modi Government has secured long term interest of farmers at World Trade Organization.

FARMER EMPOWERNMENT:

- **Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana :** targeted achievement of irrigation scheme and water shed development (water to every farmer), sprinkler and drip (more crop per drop) irrigation scheme.
- **Deen Dayal Upadhyaya Gram Jyoti Yojana –** separate feeder to provide electricity to agriculture and villages.
- **Scheme for distribution of 3 crore pump sets –** improvement in irrigation facilities and increase in agriculture income.
- **Direction to the States in July, 2015** – under MGNREGA at least 60 per cent of the amount would be spent on agriculture works.
- **Soil Health Card:** healthy soil – green farm, 80 lakh soil health cards distributed, target to give to all farmers by March, 2017.
- **Neem Coated Urea –** to reduce the use and increasing dependence of fertilizers.
- **New Fertilizer Policy –** to prevent the short fall in fertilizer and increase in fertilizer production to ensure full availability.

- **To develop National Agriculture Market with states:** Establishment of e-platform.
- **Direction to State Governments in July 2015–** minimum 60 % NREGA funds to be utilized for agriculture works.
- **Kisan TV –** 7 days 24 hour channel to help data to farmers on weather, Kisan Mandi and other aspects.
- A provision of Rs. 75 Crore as central share has been made in the budget for the first time for **National Agriculture Forestry Programme**. It will give impetus to 'med per ped'.

FARMER PROGRESS:

- **Paramparagat Krishi Vikas Yojana–** to promote organic farming, for the first time
- **Blue Revolution –** growth rate in the fisheries sector increased from 5.8% to 7.25%.
- **White Revolution–** increase in milk production from 146 million tonne to 160 million tonne.
- **Rashtriya Gokul Mission –** Sanctioned proposals worth Rs. 550 cr in 18 months for development and conservation of indigenous breeds and two National Kamdhenu Breeding Centres, with an allocation of Rs 50 crores.
- A provision of Rs. 75 crore as central share has been made in the budget of 2016-17 for the first time for **National Agriculture Forestry** Program. It will give impetus to 'med par ped'.
- **Four New Projects –** Rs. 850 crore have been provided for in the new budget of 2016-17, Livestock Sanjivani, Nakul Swasthan Patra, e-livestock haat and Rastriya Indigenous Breeds Genomic Centre.
- **Deen Dayal Antodaya Mission** - Every block affected from drought and natural calamities will work as special block. Self help groups will be constituted. Cluster privileges team will be constituted under MNREGA which will ensure water conservation and management of natural resources. These districts will be given priority under Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana.
- **Shayam Prasad Mukherjee** - for development of infrastructure in villages. 300 rural urban clusters will be developed in which agriculture processing, agriculture market, godowns and warehouses will be constructed.

प्रधानमंत्री फ

श्री नरेन्द्र मोदी
प्रधानमंत्री

हर तरह के अनाज, तिलहन
और सालाना व्यावसायिक/बागवानी
फसल का बीमा।

फसल

उपज के पूरे मूल्य
बीमा मूल्य कम न

अधिकतम
2%
प्रीमियम

खरीफ फसल
के लिए

फसल

खाद्यान्न एवं तिलहन फसलों
सालाना व्यावसायिक/ब
प्रीमियम 5 फीस
प्रीमियम की बाकी

किसान

नुकसान का
मुआवजा
न घटाया जाएगा
न काटा जाएगा।

ओला पड़ना, जमीन ध
जलभराव से ह
नुकसान का खेतवार

बीमा के लिए अपने निकटतम बैंक शाखा, कृषि सहकारिता समिति, बीमा कम्पनी या उनके एजेंट से सम्पर्क करें।
अधिक जानकारी हेतु : **http:www.agri-insurance.gov.in** देखें

फसल बीमा योजना

र बीमा
य का बीमा होगा,
नहीं किया जाएगा।

फसल बुवाई से पहले,
खड़ी फसल और कटी
फसल में जोखिम का
बीमा कवर।

बीमित

अधिकतम
1.5%
प्रीमियम

रबी फसल
के लिए

के लिए एक मौसम एक दर।
ागवानी फसलों के लिए
दी से ज्यादा नहीं।
रकम सरकार देगी।

सुरक्षित

धंसना और
हुए
आकलन।

बीमा दावों का भुगतान सीधे
किसानों के बैंक खाते में
जमा हो जाएगा।

सत्यमेव जयते

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
भारत सरकार

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग
http://agricoop.nic.in

पशुपालन, डेयरी एवं मात्स्यिकी विभाग
http://dahd.nic.in ; http://dadf.gov.in

किसानों के लिए पोर्टल
http://farmer.gov.in

किसानों के लिए मोबाइल सेवाएं
http://mkisan.gov.in

किसान कॉल सेंटर
1800-180-1551

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
http://www.icar.org.in